ATISHI
Minister
Education, Higher Education, TTE,
Finance, Planning, Revenue, PWD, Water,
Power, Services, Vigilance, Public Relations,
Law, Justice & Legislative Affairs

आतिशी
मंत्री
शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा,
वित्त, योजना, राजस्व, लोक निर्माण विभाग,
जल, ऊर्जा, सेवाएँ, सतर्कता, जनसंपर्क,
विधि, न्याय और विधायी मामले

सत्यमेव जयते

GOVT. OF NCT OF DELHI
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
DELHI SECTT, I.P. ESTATE,
दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट,
NEW DELHI-110002
नई दिल्ली-110002
Email : atishi.delhi@nic.in

D.O. No. MINISTER(WATER)/3308
Date : 19TH JUNE 2024

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

देश के कई हिस्सों में इस बार भीषण गर्मी है। दिल्ली भी उनमें से एक है, जहाँ बर्दाश्त करने की क्षमता से भी कहीं ज़्यादा गर्मी है। आपको मालूम ही होगा कि 29 मई को दिल्ली का तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस था, जो अभूतपूर्व था। कल का तापमान 47 डिग्री था। रात को 10 बजे भी तापमान 41 डिग्री था। दिल्ली में इतनी गर्मी पिछले 100 सालों में नहीं पड़ी। इतनी तपती हुई गर्मी में दिल्लीवालों की पानी की आवश्यकता बढ़ गई है। लेकिन जब दिल्लीवालों को ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत है, दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। दिल्ली में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है।

आख़िर दिल्ली में पानी की कमी क्यों हो रही है? दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 MGD है, इसमें से हरियाणा से 613 MGD पानी आता है। लेकिन पिछले 2 हफ़्तों से हरियाणा से पानी आना बहुत कम हो गया है। 18 जून के आँकड़े देखे तो, मात्र 513 MGD पानी हरियाणा द्वारा दिल्ली में भेजा गया। यानि दिल्ली को 100 MGD पानी कम मिल रहा है। 1 MGD पानी से एक दिन में तक़रीबन 28,500 लोगों को पानी मिलता है। 100 MGD पानी की कमी से 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। यानि हरियाणा सरकार ने 28 लाख दिल्लीवालों का पानी रोक दिया है।

प्रधानमंत्री जी: आप ही बताइए, क्या 28 लाख दिल्लीवालों को प्यासा रखना सही है?

जब दिल्ली में पानी की कमी हुई तो मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उनसे अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए अनुरोध किया। पर हरियाणा सरकार ने पानी नहीं छोड़ा। मैंने हिमाचल प्रदेश के सामने हाथ जोड़े और दिल्ली के लिए पानी हेतु निदेवन किया। हिमाचल प्रदेश अपना अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार है, पर वो भी हरियाणा से होते हुए आना है। हरियाणा सरकार ने हिमाचल से आ रहा पानी देने से भी इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार इन 28 लाख लोगों को पानी दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का संकट है, पर उसके बावजूद हरियाणा सरकार ने दिल्लीवालों को 100 MGD पानी नहीं दिया। हमारे विधायक केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्री से मिलने भी गए, परंतु वे मिले नहीं। दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारी कल हरियाणा सरकार के अधिकारियों से मिलने चंडीगढ़ भी गए, पर फिर भी हरियाणा ने पानी नहीं दिया।

सत्यमेव जयते

प्रधानमंत्री जी: दिल्ली के लोग बहुत परेशान है। अब मुझसे ये परेशानी देखी नहीं जाती। मैंने हर संभव प्रयास कर लिया, पर हरियाणा सरकार दिल्लीवालों को पानी देने को तैयार नहीं है। अब आप से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रही हूँ कि आप दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी दिलवाइये।

दिल्ली के इतिहास में कभी इतना पानी का संकट नहीं हुआ। इस भीषण गर्मी में दिल्ली के लोग एक-एक बूँद पानी के लिए तरस रहे हैं। जब मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब भी कुछ बार पानी की कमी हुई; पर पानी का इतना संकट कभी नहीं हुआ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार ने 28 लाख दिल्लीवालों को पानी के लिए तरसा दिया है।

मुझे पता है कि हरियाणा के लोग भी भीषण गर्मी में परेशान हैं। उन्हें भी पानी की ज़रूरत है। लेकिन हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है, और उन्हें 6500 MGD पानी मिलता है। दिल्ली की आबादी भी 3 करोड़ है, और हमें मात्र 1050 MGD पानी मिलता है। अगर हरियाणा सरकार दिल्लीवालों को 100 MGD पानी दे भी दे, तो ये उनके पानी का सिर्फ़ 1.5% है।

मेरे हर संभाव प्रयास के बाद भी हरियाणा सरकार दिल्ली को यह 100 MGD पानी नहीं दे रही। अब बूँद-बूँद पानी के लिए तड़पती दिल्ली के लोगों की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। मेरी हाथ जोड़ कर आपसे विनती है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और हरियाणा सरकार से दिल्ली के लोगों को उनके हक़ का पानी दिलवाएँ।

पानी न मिलने की स्थिति में 21 जून से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह करना पड़ेगा और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठना पड़ेगा। मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, पर अब दिल्लीवालों का कष्ट मैं सहन नहीं कर सकती।

आदर सहित

भवदीय

(आतिशी)

श्री नरेन्द्र मोदी जी,
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली